याचिकाकर्ता:प्रबंधन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड

बनाम

प्रत्यर्थी:बी. सोमायाजुलु और अन्य

फैसले की तारीख: 18/04/1963

बेंच: पी.बी. गजेंद्रगढ़कर, के.एन वांचू, केसी गुप्ता

औद्योगिक विवाद--'श्रमजीवी पत्रकार"--निर्माण-परीक्षण निर्धारित--अंशकालिक कर्मचारी निर्धारित परीक्षण को पूरा करता है

यदि, धारा के दायरे से बाहर किया जा सकता है--'एवोकेशन,"(व्यवसाय) का अर्थ --वर्किंग जर्नलिस्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1955 (1955 का 1), धारा. 2 (बी).

हेडनोट:गुंटूर में एक संवाददाता के रूप में प्रत्यर्थी की सेवाएँ अपीलार्थी के अधीन समाप्त कर दी गई। श्रमजीवी पत्रकार संघ आंध्र प्रदेश, एलुरु ने प्रत्यर्थी का पक्ष लेकर अभिकथित किया कि बिना किसी औचित्य के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी और वह एक श्रमजीवी पत्रकार के रूप में बहाली और क्षतिपूर्ति के हकदार थे। विवाद को सरकार द्वारा श्रम न्यायालय गुुंटूर आंध्रप्रदेश भेजा गया। अपीलकर्ता द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष प्राम्भिक आपत्तियाँ उठाई गई जिन्हें सभी को अस्वीकार कर दिया गया। गुण-दोष के आधार पर, अपीलकर्ता ने तर्क दिया

कि एक मोफुसिल संवाददाता का पेशा प्रत्यर्थी का प्रमुख व्यवसाय नहीं था और इसलिए अधिनियम की धारा 2(b) के अधीन वह श्रमजीवी पत्रकार की स्थिति के लाभ का दावा नहीं कर सकता। श्रम न्यायालय ने प्रत्यर्थी के विरूद्घ निर्णय पारित किया। प्रत्यर्थी के खिलाफ मामला केवल इस आधार पर निर्णित हुआ कि एक पत्रकार अंशकालिक कार्यकर्ता के रूप में होने पर उसे कामकाजी पत्रकार नहीं माना जा सकता, और इसने इस प्रश्न पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला कि क्या सेवा समाप्ति के समय उनका प्रमुख व्यवसाय धारा 2(b) के तहत परिभाषा द्वारा निर्धारित परीक्षण की संतुष्टि कर रहा था।

इस फैसले को प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि प्रत्यर्थी धारा 2(b)के तहत एक कामकाजी पत्रकार था और इसलिए निर्णय को रद्द कर दिया। प्रमाण पत्र द्वारा अपील होने पर इसमें अपीलकर्ता के मुख्य तर्क यह थे कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को धारा 2(b) के अधीन कामकाजी पत्रकार मानने में गलती की थी।

धारित किया कि जब भी किसी समाचार पत्र में काम करने वाला कर्मचारी कामकाजी पत्रकार होने की स्थिति का दावा करता है तो उसेपहले यह स्थापित करना होगा कि वह एक पत्रकार है, और फिर यह कि पत्रकारिता उनका प्रमुख व्यवसाय है और उसे ऐसे पत्रकार के रूप में ही

नियुक्त किया गया है। इस तथ्य को सिद्ध करने में कि वह एक पत्रकार है, कर्मचारी बाद में निर्दिष्ट धारा 2(b) के द्वितीय खण्ड में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों को इसके अलावा और कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वे उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी श्रेणी में सम्मिलित हैं। परन्तु यह केवल उनकी पत्रकार के रूप में हैसियत साबित करता है। उन्हें अभी भी यह साबित करना बाकी है कि उनका मुख्य पेशा एक पत्रकार का है और उन्हें उसी अखबार द्वारा इस तरह नियोजित किया गया है।

बनाई गई कृत्रिम विस्तार का उद्देश्य किसी पत्रकार को कामकाजी पत्रकार मानने से पहले समावेशी खण्ड द्वारा परिभाषा में विहित दो शर्तों को छोड़ देना नहीं है।

अधिनियम की धारा 2(b) के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उद्योग शब्द के अर्थ को शब्दकोश या व्युत्पत्ति के आधार पर अंगीकृत करना अनुचित होगा।

आगे धारित किया गया आम तौर पर अधिनियम की धारा 2(b) द्वारा विचारित रोजगार के संदर्भ में पूर्णकालिक रोजगार होता है लेकिन अंशकालिक रोजगार को उक्त धारा से बाहर नहीं रखा गया। धारा 2(बी) के निष्पक्ष निर्वचन पर उस भाग को बनाए रखना असंभव होगा कि अंशकालिक कर्मचारी जो धारा द्वारा निर्धारित परीक्षण को पूरा करता है, को सिर्फ इसलिए इसके दायरे से बाहर किया जा सकता है क्योंकि उसका

रोजगार अंशकालिक है।

वर्तमान मामले में, मुद्दे को साबित करने का दायित्व कि क्या एक संवाददाता का कार्य उसका प्रधान व्यवसाय था, के आलोक में प्रासंगिक तथ्यों के साथ प्रासंगिक समय पर व्यवसाय के संबंध में यह मुद्दा भी कि क्या वह अपीलकर्ता के एकमात्र रोजगार में था, प्रत्यर्थी में निहित है और यह तभी संभव है जब वह इस तथ्य को स्थापित कर दे कि वह एक श्रमजीवी पत्रकार है, उस अनुतोष का निर्धारण करने के लिए जिसका वह हकदार है, उत्पन्न हो सकता है।

<u>निर्णय:</u>

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1962 की सिविल अपील संख्या 202।

1958 की रिट याचिका संख्या 677 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 10 मार्च 1961 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ता की ओर से एवी विश्वनाथ शास्त्री, जयराम और आर. गणपति अय्यर।

प्रत्यर्थी नंबर 1 के लिए वीके कृष्ण मेनन, एमके राममूर्ति, आरके गर्ग, एससी अग्रवाल और डीपी सिंह।

प्रत्यर्थी नंबर 2 के लिए केआर चौधरी और पीडी मेनन।

18 अप्रैल 1963

अदालत का फैसला न्यायमूर्ति गजेंद्रगढ़कर द्वारा सुनाया गया।

इस अपील में जो प्रमुख प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी बी. सोमयाजुलु अधिनियम की धारा 2(b) के तहत एक कामकाजी पत्रकार हैं। श्रमजीवी पत्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1955, (1955 का क्रमांक 1) (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अधीन श्रमजीवी पत्रकार है। 19 फरवरी, 1935 को, अपीलकर्ता, एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा प्रत्यर्थी को गुंटूर में एक संवाददाता के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने यह काम 20 अक्टूबर, 1955 तक लगातार किया, जिस दिन उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके बाद आंध्र यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, एलुरु ने प्रत्यर्थी का मामला उठाया और आरोप लगाया कि उनकी सेवाओं को अपीलकर्ता ने बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के समाप्त कर दिया था और एक कामकाजी पत्रकार के रूप में, वह उस अवधि के लिए बहाली और मुआवजे के हकदार थे, जिसके दौरान अपीलकर्ता द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त करने के पारित आदेश के परिणामस्वरूप उसे काम करने की अनुमति नहीं दी गई। इस विवाद को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा श्रम न्यायालय, गुंटूर में निर्णय के लिए भेजा गया था। निर्णय के लिए भेजा गया प्रश्न यह था कि क्या गुंटूर में इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों के संवाददाता श्री बी सोमयाजुलु की सेवाओं की समाप्ति उचित थी? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष के हकदार थे ? श्रम न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी ने दावा किया कि बहाली के अलावा, उसे 13

अक्टूबर, 1955 से 1 मई, 1956 तक 75/-रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए और उसके बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर बहाली की तारीख तक भी दिया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता ने कई आधारों पर इस दावे का खंडन किया। इसमें आग्रह किया गया कि श्रम न्यायालय के पास इस संदर्भ पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि प्रत्यर्थी की नियुक्ति मद्रास में की गई थी, उसे देय धन मद्रास से भेजा गया था, और इसलिए, उपयुक्त सरकार जो संदर्भ दे सकती थी वह थी मद्रास सरकार, न कि आंध्र प्रदेश सरकार। इस दलील को श्रम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यह भी आग्रह किया गया कि संदर्भ अमान्य था क्योंकि संदर्भ के आदेश में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 (1) (सी) का उल्लेख नहीं था जिसके तहत संदर्भित करने की शक्ति का प्रयोग किया गया था। श्रम न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया। तब यह आक्षेप लगाया गया था कि निर्णय के लिए श्रम न्यायालय को भेजा गया विवाद एक व्यक्तिगत विवाद था और किसी भी संघ द्वारा उचित रूप से प्रायोजित नहीं किया गया था। इस दलील से भी श्रम न्यायालय प्रभावित नहीं हुआ और इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई सभी प्रारंभिक आपत्तियाँ खारिज कर दी गईं।

गुण-दोष के आधार पर, अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 2(b) के तहत एक कामकाजी पत्रकार नहीं था। इस दलील के समर्थन में अपीलकर्ता ने कहा कि प्रत्यर्थी एक अंशकालिक संवाददाता था जो किसी विशेष समाचार पत्र प्रतिष्ठान से जुड़ा नहीं था और एक साल या उसके बाद उसे अपीलकर्ता के प्रकाशनों जैसे एक्सप्रेस समाचार पत्र, दीनामणि के विक्रय एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। और आंध्र प्रदेश गुंटूर में जो असाइनमेंट उन्हें 6000 रुपये जमा करने पर दिया गया था। जिसे बाद में बढ़ाकर रु. 7,000/- कर दिया गया। अपीलकर्ता के अनुसार, ऐसे विक्रय एजेंट के रूप में, प्रत्यर्थी औसतन लगभग रूपए 1,500/- प्रति माह कमीशन के रूप में कमा रहा था, जबकि एक संवाददाता के रूप में उन्हें पहले पदानुक्रम के आधार पर भुगतान किया गया था और बाद में मानदेय 50/-रुपये निर्धारित किया गया था। जिसे बाद में बढ़ाकर रु. 75/- प्रतिमाह कर दिया गया। यह बाद वाली राशि उन्हें उनकी सेवाएं समाप्त होने तक भुगतान की गई थी। इसलिए, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि मोफुसिल संवाददाता का पद प्रत्यर्थी का मुख्य व्यवसाय नहीं है, और इसलिए, वह धारा 2(b) के तहत एक कामकाजी पत्रकार की स्थिति के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। श्रम न्यायालय ने माना कि अंशकालिक कर्मचारी अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। इसने संयोगवश उस कमीशन का भी उल्लेख किया जो प्रत्यर्थी को बिक्री एजेंट के रूप में प्राप्त हुआ था और इस आशय की कुछ टिप्पणियाँ की कि एक

संवाददाता के रूप में उसके काम के लिए प्रत्यर्थी को भुगतान उस कमीशन से बहुत कम था जो उसे बिक्री एजेंट के रूप में अपीलकर्ता से प्राप्त हुआ था। यह सामान्य बात है कि संवाददाता के रूप में प्रत्यर्थी की सेवाएं समाप्त होने से कुछ समय पहले, उसकी बिक्री एजेंसी भी समाप्त हो गई थी। श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से, यह स्पष्ट है कि श्रम न्यायालय ने प्रत्यर्थी के खिलाफ मामले का फैसला केवल इस आधार पर किया कि अंशकालिक कर्मचारी के रूप में उसे एक कामकाजी पत्रकार नहीं माना जा सकता है, और उसने इस प्रश्न पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला कि क्या उस समय जब उनकी सेवाएँ समाप्त की गई थीं, उनका मुख्य व्यवसाय धारा 2(b) के तहत परिभाषा द्वारा निर्धारित परीक्षण को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है।

श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक रिट याचिका द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रत्यर्थी धारा 2(b) के तहत एक कामकाजी पत्रकार है और इसलिए, इसने श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/पंचाट को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निपटान के लिए पक्षों के बीच की कार्यवाही को श्रम न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने के लिए कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से आदेश का प्रभाव है। इस निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता उक्त उच्च

न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर इस न्यायालय में आया है और अपीलकर्ता की और से श्री शास्त्री द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती कि प्रत्यर्थी धारा 2(b) के तहत एक कामकाजी पत्रकार था।

जो अधिनियम पक्षकारों के बीच की इस कार्यवाही पर लागू होता है वह 1955 का अधिनियम संख्याक 1 था। यह अधिनियम 12 मार्च, 1955 को लागू हुआ। इसमें केवल 3 धाराएँ हैं। धारा 1 ने अधिनियम का शीर्षक दिया; धारा 2 खंड (ए) और (बी) द्वारा 'समाचार पत्र' और 'श्रमिक पत्रकार' को परिभाषित किया गया और धारा 3 ने एक सामान्य प्रावधान किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के प्रावधान कामकाजी पत्रकारों पर या उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे लागू होते हैं, या उस अधिनियम के अर्थ के भीतर कामगारों के संबंध में लागू होते हैं। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की योजना समाचार पत्र और कामकाजी पत्रकार को परिभाषित करना और औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को कामकाजी पत्रकारों पर लागू करना था।

इस अधिनियम के बाद श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम , 1955 (संख्या 45, 1955) लागू किया गया। इस अधिनियम में 21 धाराएं हैं और यह औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों से अलग, कामकाजी पत्रकारों पर लागू होने वाले कुछ

विशिष्ट प्रावधान बनाता है। इस अधिनियम की धारा 2 (एफ) एक श्रमजीवी पत्रकार को परिभाषित करती है। उक्त अधिनियम की धारा 2(f) द्वारा निर्धारित परिभाषा पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 2(b) द्वारा निर्धारित परिभाषा के समान है। और इसलिए, वर्तमान अपील के प्रयोजनों के लिए, पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 2(b) की परिभाषा के दायरे और प्रभाव के बारे में हम जो भी कहते हैं, उक्त धारा 2(f) द्वारा निर्धारित परिभाषा पर लागू होगा। इस बाद वाले अधिनियम की धारा 3 औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के प्रावधानों को कामकाजी पत्रकारों पर लागू करती है। धारा, 4 और 5 छंटनी और ग्रेच्युटी के संबंध में विशेष प्रावधान करते हैं। धारा 6 काम के घंटे निर्धारित करती है। धारा 7 छुट्टियों की समस्या से संबंधित है । धारा 8 वेतन बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है। धारा 9 वेतन निर्धारण से संबंधित है। धारा 10 'बोर्ड के निर्णय के प्रकाशन और उसके प्रारंभ की आवश्यकता से संबंधित है, जबकि धारा 11 बोर्ड की शक्तियों और प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 12 बोर्ड के निर्णय को बाध्यकारी बनाती है और धारा 13 सरकार को मजदूरी की अंतरिम दरें तय करने की शक्ति देता है। ये प्रावधान अध्याय II में निहित हैं। अध्याय III में 2 धाराएँ 14 और 15 शामिल हैं और वे समाचार पत्र कर्मचारियों पर औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम , 1946 और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम , 1952 के प्रावधानों को लागू करते हैं। अध्याय IV में विविध प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि संबंधित धारा के तहत नियोक्ता से देय धन

की वसूली के लिए धारा 17 , धारा18 के तहत जुर्माना और धारा 19 के तहत क्षतिपूर्ति, धारा 20 केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, और धारा। 21 पिछले अधिनियम को निरस्त करता है।

इस प्रश्न का निस्तारण करने में कि क्या प्रत्यर्थी को श्रमजीवी पत्रकार कहा जा सकता है, अधिनियम की धारा 2(b) द्वारा निर्धारित परिभाषा को पढ़ना आवश्यक है।

"श्रमिक पत्रकार' का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मुख्य पेशा पत्रकारिता है और जो किसी समाचार पत्र के उत्पादन या प्रकाशन के लिए किसी प्रतिष्ठान में या किसी समाचार एजेंसी में या उसके संबंध में कार्यरत है। या किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए सामग्री की आपूर्ति करने वाला सिंडिकेट, और इसमें एक संपादक, एक नेता-लेखक, समाचार संपादक, उप-संपादक, फीचर-लेखक, कॉपी-परीक्षक, रिपोर्टर, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, समाचार फोटोग्राफर और प्रूफ-रीडर शामिल हैं लेकिन इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है जो--

(i) मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत है, या

(ii) पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित होने पर, या तो कार्यालय से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या उसमें निहित शक्तियों के कारण, मुख्य रूप से प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य करता है।

यह स्पष्ट है कि धारा 2(b) द्वारा निर्धारित परिभाषा दो भागों से

मिलकर बनी है; पहला भाग बताता है कि एक श्रमजीवी पत्रकार का क्या मतलब है, और दूसरा भाग एक कृत्रिम विस्तार द्वारा समाचार पत्र कर्मचारियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को इसके दायरे में लाता है। यह ध्यान दिया जाएगा कि पहला भाग दो शर्तों का प्रावधान करता है जिन्हें एक पत्रकार द्वारा श्रमजीवी पत्रकार माने जाने से पहले पूरा करना होगा। पहली शर्त यह है कि उसे एक पत्रकार होना चाहिए जिसका मुख्य पेशा पत्रकारिता का है। और दूसरी शर्त यह है कि उसे वहां निर्दिष्ट किसी भी प्रतिष्ठान में या उसके संबंध में नियोजित किया जाना चाहिए। हमारे निर्णय के लिए पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या परिभाषा के पहले भाग द्वारा निर्धारित दो शर्तें, सम्मिलित खंड द्वारा किए गए कृत्रिम विस्तार द्वारा परिभाषा में शामिल समाचार पत्र कर्मचारियों की श्रेणियों को नियंत्रित करती हैं। उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि जिन कर्मचारियों की श्रेणियों को नाम से परिभाषा में शामिल किया गया है, उन्हें पहले भाग द्वारा निर्धारित दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। तर्क यह है कि चूंकि एक संवाददाता को, उदाहरण के लिए, दूसरे खंड में नामित किया गया है, विधायिका का पूरा उद्देश्य पहले भाग द्वारा निर्धारित दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता के बिना उसे एक कामकाजी पत्रकार बनाना था। हमारी राय में, यह निर्वचन स्पष्ट रूप से गलत है। दूसरे खंड का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि उस खंड में निर्दिष्ट कर्मचारी पत्रकार हैं और इससे अधिक कुछ नहीं। अधिनियम में

"पत्रकार" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और विधायिका ने सोचा है कि यही विवाद उत्पन्न हो सकता है कि कोई विशेष समाचार पत्र कर्मचारी पत्रकार था या नहीं। निस्संदेह, किसी संपादक या नेता-लेखक, या समाचार संपादक या उप-संपादक को पत्रकार माने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती; लेकिन यह स्पष्ट रूप से आशंका थी कि एक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, उदाहरण के लिए, एक संवाददाता, एक प्रूफ रीडर, एक कार्टूनिस्ट, एक रिपोर्टर, एक कॉपी-परीक्षक, या एक फीचर लेखक के मामले में, और इसलिए, विधायिका ने सावधानी बरती विशेष रूप से यह प्रावधान करते हुए कि बाद वाले खंड में सूचीबद्ध कर्मचारियों को धारा 2(b) द्वारा निर्धारित परिभाषा के प्रयोजन के लिए पत्रकार माना जाएगा। सम्मिलित खंड द्वारा किए गए कृत्रिम विस्तार का उद्देश्य किसी पत्रकार को श्रमजीवी पत्रकार माने जाने से पहले परिभाषा द्वारा निर्धारित दो मुख्य शर्तों को समाप्त करना नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विस्तारित अर्थ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी इस तरह नियोजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पहले खंड द्वारा निर्धारित दूसरी आवश्यकता कि पत्रकार को किसी समाचार पत्र के उत्पादन या प्रकाशन के लिए किसी प्रतिष्ठान में या उसके संबंध में नियोजित किया जाना चाहिए, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट है, बाद वाले खंड के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों द्वारा तुष्ट होनी होगी, क्योंकि जब तक अखबार प्रतिष्ठान द्वारा कोई रोजगार देय नहीं होता, तब तक नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध

उत्पन्न नहीं हो सकता है, और बाद वाले खंड में निर्दिष्ट पत्रकार, प्रबंधन करने वाले नियोक्ता के लिए कामकाजी पत्रकार की स्थिति का दावा नहीं कर सकते हैं। एक बार यह एहसास हो जाए कि. रोजगार का परीक्षण बाद के खंड में निर्दिष्ट कर्मचारियों को भी नियंत्रित करना चाहिए, यह स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की थी कि श्रमजीवी पत्रकार की विस्तारित कृत्रिम परिभाषा उक्त परिभाषा के पहले भाग द्वारा निर्धारित दोनों शर्तों से दूर है। इसीलिए हम सोचते हैं कि "शामिल" शब्द का विस्तार केवल इस संदेह को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था कि उक्त खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति पत्रकार हैं या नहीं। रोजगार की स्थिति के बारे में जो सच है, वह दूसरी शर्त के बारे में भी उतना ही सच है कि एक पत्रकार केवल तभी कार्यरत पत्रकार हो सकता है, जब यह दिखाया जाए कि पत्रकारिता उसका प्रमुख व्यवसाय है। दूसरे शब्दों में, स्थिति यह है कि जब भी समाचार पत्र प्रतिष्ठान में काम करने वाला कोई कर्मचारी श्रमजीवी पत्रकार होने का दावा करता है, तो उसे पहले यह स्थापित करना होगा कि वह एक पत्रकार है, और फिर पत्रकारिता उसका प्रमुख व्यवसाय है और उसे ऐसे पत्रकार के रूप में नियोजित किया गया है। . इस तथ्य को साबित करने के लिए कि वह एक पत्रकार है, बाद वाले खंड में निर्दिष्ट कर्मचारियों को इससे अधिक कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वे उक्त खंड में निर्दिष्ट एक या अन्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यह केवल पत्रकार के रूप में उनकी स्थिति को साबित करता है; उन्हें अभी भी यह

दिखाना है कि उनका मुख्य पेशा एक पत्रकार का है और उन्हें संबंधित समाचार पत्र प्रतिष्ठान द्वारा उसी रूप में नियुक्त किया गया है।

यह हमें इस प्रश्न पर ले जाता है कि व्यवसाय का क्या अर्थ है? उच्च न्यायालय ने सोचा कि "एवोकेशन" शब्द का शब्दकोषीय अर्थ, जिससे पता चलता है कि इसका अर्थ "किसी के नियमित रोजगार से ध्यान भटकाना या अलग होना है, को धारा 2(b) के संदर्भ में अपनाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में, उच्च न्यायालय ने आधुनिक अंग्रेजी उपयोग में फाउलर के एक अंश का हवाला दिया है। फाउलर कहते हैं, "एवोकेशन मूल रूप से एक बुलावा, एक रुकावट, एक व्याकुलता है, जिसे कुछ समय के लिए आमतौर पर व्यवसाय या उद्यम के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसके साथ यह उचित रूप से विपरीत है। यह दुरुपयोग अब कम प्रचलित है, और इस शब्द का आम तौर पर बहुवचन में उपयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति का व्यवसाय वे चीजें हैं जिनके लिए वह समय समर्पित करता है, सामान्य रूप से उसके कार्य या व्यस्तताएं, वे मामले जिन्हें उसे देखना होता है; उसके व्यवसाय को न तो उसके व्यवसाय से बाहर रखा गया है, न ही आवश्यक रूप से इसमें शामिल किया गया है।" "एवोकेशन" शब्द के इस शब्दकोश अर्थ को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने धारित किया है कि भले ही प्रत्यर्थी को धारा 2(b) के पहले भाग द्वारा निर्धारित पहली शर्त को पूरा करना होगा, यह माना जा सकता है कि वह उक्त परीक्षण से संतुष्ट है, क्योंकि उसके

मामले में एक संवाददाता के काम को उसके नियमित रोजगार से विचलित करने के अर्थ में सुरक्षित रूप से उसका प्रमुख व्यवसाय कहा जा सकता है। हमारी राय में धारा 2(b) के संदर्भ पर उचित ध्यान दिए बिना "एवोकेशन" शब्द के शब्दकोश अर्थ को यंत्रवत् लागू करने में उच्च न्यायालय ने कुछ हद तक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। किसी को केवल धारा 2(b) में प्रयुक्त शब्द "एवोकेशन" को समझने के लिए परिभाषा को पढ़ना है। जिसका मतलब संभवतः किसी के नियमित रोजगार से ध्यान भटकाना नहीं हो सकता। इसके विपरीत, इसका स्पष्ट अर्थ है किसी का व्यवसाय, उद्यम या पेशा। धारा 2(b) में अंतर्निहित स्पष्ट विचार यह है कि यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए संवाददाता का, और साथ ही कोई अन्य पेशा या पेशा अपना रहा है, मान लीजिए वकील का, तो यह केवल वहीं है जहां उसे 'पत्रकार' कहा जा सकता है कि यह उनका प्रमुख पेशा था कि उन्हें एक श्रमजीवी पत्रकार का दर्जा सौंपा जा सकता है। धारा 2(b) का स्पष्ट उद्देश्य होते हुए "एवोकेशन" शब्द के शब्दकोश या व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ को अपनाना अनुचित होगा। हमें यह जोड़ना चाहिए कि प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित हुए श्री मेनन ने इस बिंदु से निपटने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए, जब यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी पत्रकार को श्रमजीवी पत्रकार कहा जा सकता है, तो यह दिखाना होगा कि जिस भी प्रकार की पत्रकारिता पर विचार किया गया है, वह एक कामकाजी पत्रकार

की स्थिति का दावा करने वाले व्यक्ति का मुख्य व्यवसाय है और इसमें स्वाभाविक रूप से एक पत्रकार के करियर को आगे बढ़ाने से उसके द्वारा किए गए लाभ की तुलना में अन्य पेशों व व्यवसायों में उसके द्वारा किए गए लाभ की जांच शामिल होगी। यह स्पष्ट है कि यह परीक्षण केवल शैक्षणिक होगा और पूर्णकालिक पत्रकारों के मामले में इसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मामलों में स्पष्ट धारणा यह होगी कि उनका पूर्णकालिक रोजगार उनका प्रमुख व्यवसाय है और पत्रकारिता से उनकी आय की तुलना अन्य स्त्रोतों से आय से करने का कोई सवाल ही नहीं है। वास्तव में, ऐसे पूर्णकालिक पत्रकारों की कार्यशील पत्रकार की स्थिति प्रभावित नहीं होगी, भले ही कुछ मामलों में ऐसे रोजगार से उन्हें प्राप्त आय, उदाहरण के लिए, उनकी पैतृक संपत्ति से प्राप्त आय से कम पाई जाए। यह परीक्षण केवल अंशकालिक आधार पर कार्यरत पत्रकारों के मामले में महत्व रखता है।

रोजगार की दूसरी आवश्यकता पर वापस लौटते हुए, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं, स्पष्ट रूप से धारा 2(b) के उत्तरार्ध के तहत सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के लिए, यदि वे कामकाजी पत्रकारों का दर्जा चाहते हैं, तो यह स्पष्ट है कि रोजगार साबित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ही उनके और समाचार पत्र प्रतिष्ठान के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध बनाएगा। जब तक कोई रोजगार न हो, सेवा की कोई शर्त नहीं हो सकती और अधिनियम के तहत कोई दावा करने की कोई गुंजाइश नहीं

होगी। इस प्रकार रोजगार की आवश्यकता पार्टियों पक्षकारों के बीच सहमत सेवा की शर्तों को निर्धारित करती है जिसके अधीन स्वामी और नौकर का रिश्ता अस्तित्व में आता है। इस संदर्भ में, रोजगार में अनिवार्य रूप से विशेष रोजगार को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि एक कामकाजी पत्रकार दो नियोक्ताओं की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उन लाभों के साथ असंगत होगा जो वह अधिनियम के तहत अपने नियोक्ता से दावा करने का हकदार है। छँटनी, मुआवज़े, या ग्रेच्युटी, या काम के घंटे, या छुट्टी का लाभ उठाएँ; एक पत्रकार के लिए दो या दो से अधिक नियोक्ताओं से इन लाभों का दावा करना कैसे संभव है? अधिनियम की पूरी योजना जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को कामकाजी पत्रकारों पर लागू किया गया है, आवश्यक रूप से नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते को मानती है और इसका मतलब नियोक्ता द्वारा पक्षकारों के बीच सहमत सेवा की शर्तों और शर्तों पर एकमात्र रोजगार होना चाहिए। आम तौर पर, धारा 2(b) द्वारा पूर्णकालिक रोजगार पर विचार किया जाता है, लेकिन अंशकालिक रोजगार को धारा 2(b) से बाहर नहीं रखा गया है। अधिकांश कर्मचारी जो या ता धारा 2(b) के पहले खंड के अंतर्गत आते हैं या धारा 2(b) के बाद के खंड द्वारा निर्धारित कृत्रिम विस्तार के तहत भी पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे। लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से संभव है कि एक समाचार-फोटोग्राफर, उदाहरण के लिए, या एक कार्टूनिस्ट आवश्यक रूप से पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हो सकते हैं। ऐसा

प्रतीत होता है कि समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में पूर्णकालिक कर्मचारियों को ही कामकाजी पत्रकार के रूप में रखना आधुनिक चलन है; लेकिन धारा 2(b) के निष्पक्ष निर्वचन पर हमें नहीं लगता कि एक अंशकालिक कर्मचारी को जो धारा 2(b) द्वारा निर्धारित परीक्षण को पूरा करता है को केवल इसलिए इसके दायरे से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि उसका रोजगार अंशकालिक है।इसलिए, स्थिति यह है कि श्रम न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने में गलती कर रहा था कि प्रत्यर्थी एक कामकाजी पत्रकार नहीं था क्योंकि वह एक अंशकालिक कर्मचारी था, जबकि उच्च न्यायालय यह मानने में गलती कर रहा था कि प्रत्यर्थी एक नियोजित कर्मचारी है। क्योंकि उसे इस कसौटी पर खरा नहीं उतरना है कि पत्रकारिता उसका प्रमुख व्यवसाय है। जैसा कि हमने माना है, प्रत्यर्थी को तभी श्रमजीवी पत्रकार कहा जा सकता है जब वह धारा 2(b) के पहले भाग द्वारा निर्धारित दो परीक्षणों को पूरा करता है। यह परीक्षण कि उन्हें एक पत्रकार के रूप में नियोजित किया जाना चाहिए था, निस्संदेह संतुष्ट होगा क्योंकि यह सामान्य आधार है कि 1935 से वह गुंटूर में अपीलकर्ता के संवाददाता के रूप में काम कर रहे हैं और अपीलकर्ता ने उन्हें जो भी भुगतान किया है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए पक्षकारों के बीच एक समझौते द्वारा भी विनियमित किया गया था; हालाँकि, अपीलकर्ता ने अपनी दलीलों में इस तथ्य पर विवाद किया है कि प्रत्यर्थी एकमात्र रूप से नियोजित था। और इसलिए, यह एक प्रश्न है जिस पर अभी भी विचारण किया जाना बाकी है। आगे का प्रश्न जिस पर

विचार किया जाना है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी अन्य परीक्षण को पूरा करता है: "कि क्या एक संवाददाता के रूप में काम करना प्रासंगिक समय में उसका प्रमुख व्यवसाय था"? परिभाषा के अनुसार प्रत्यर्थी को यह दिखाना होगा कि जिस समय उसकी सेवाएँ समाप्त की गईं, वह एक कामकाजी पत्रकार था; और इसका निर्णय केवल पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर ही किया जा सकता है। दुर्भाग्य से, हालांकि श्रम न्यायालय ने इस बिंदु पर कुछ टिप्पणियाँ की हैं, लेकिन उसने सभी सबूतों पर विचार नहीं किया है और इस संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह माना गया था कि अंशकालिक कर्मचारी के रूप में, प्रत्यर्थी धारा 2(b) से बाहर था । इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक रूप से इस आधार पर भी निष्कर्ष निकाला है, लेकिन, हमारी राय में, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक रिट याचिका से निपटने में यह तरीका नहीं अपनाना चाहिए था। इस प्रश्न पर, उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित हुआ प्रतीत होता है कि एक संवाददाता के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करने में प्रत्यर्थी ने अपने समय का एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया होगा; और यह विचार किया गया कि यह परीक्षण कि पत्रकारिता पत्रकार का प्रमुख व्यवसाय होना चाहिए, में यह परीक्षण शामिल है कि काम करने में कितना समय व्यतीत होता है? एक पत्रकार द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बिताया गया समय निस्संदेह सुसंगत हो सकता है, लेकिन यह निर्णायक नहीं हो सकता। जो

बात प्रासंगिक, सारगर्भित और निर्णायक होगी वह यह है कि अंशकालिक पत्रकार द्वारा पत्रकारिता का पेशा अपनाकर प्राप्त लाभ की तुलना में उसे अन्य व्यवसाय या पेशा अपनाने से होने वाला लाभ कितना है। मामले के इस पहलू से निपटने में, निस्संदेह इस तथ्य को ध्यान में रखना प्रासंगिक हो सकता है कि एक संवाददाता के रूप में उनकी सेवाएं समाप्त होने से कुछ महीने पहले, प्रत्यर्थी की बिक्री एजेंसी समाप्त हो गई थी, और इसलिए, श्रम न्यायालय को इस प्रश्न की जांच करनी पड़ी होगी कि क्या प्रत्यर्थी प्रासंगिक तथ्यों के आलोक में यह साबित करता है कि प्रासंगिक समय पर संवाददाता का काम उसका मुख्य व्यवसाय था। इस मुद्दे के साथ-साथ इस मुद्दे को साबित करने का दायित्व कि क्या वह अपीलकर्ता के एकमात्र रोजगार में था, प्रत्यर्थी पर है, क्योंकि उसका दावा कि वह इन आधारों पर एक कामकाजी पत्रकार है, अपीलकर्ता द्वारा विवादित है, और यह केवल यदि वह यह तथ्य स्थापित कर देता है कि वह एक श्रमजीवी पत्रकार है तो यह प्रश्न उठ सकता है कि वह किस राहत का हकदार है। इसलिए, हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं और मामले को श्रम न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित हैं कि वह इस फैसले के आलोक में पक्षकारों के बीच विवाद को कानून के अनुसार निपटाए।

खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा..।

हालाँकि, इस अपील के समाप्त करने से पहले, हम संयोगवश इस तथ्य का उल्लेख करना चाहेंगे कि धारा 2(b) द्वारा निर्धारित मुख्य व्यवसाय का परीक्षण संभवतः प्रेस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों के आधार पर विधायिका द्वारा अपनाया गया है। चरण संख्या-505 में, कामकाजी पत्रकारों के सवाल से निपटते हुए, आयोग ने कहा कि उसका विचार है कि "केवल वे लोग जिनका पेशा और आजीविका का मुख्य साधन पत्रकारिता है, उन्हें कामकाजी पत्रकार माना जाना चाहिए," और इसमें कहा गया है कि "हमने जानबूझकर ऐसा किया है।" इसमें "व्यावसायिक व्यवसाय" शब्द शामिल हैं क्योंकि हमारे सामने ऐसे मामले आए हैं जहां कानून, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कुछ अन्य व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों ने अपने समय का कुछ हिस्सा समाचार पत्रों को समाचारों की आपूर्ति और उनके लिए लेख लिखने में समर्पित किया है। ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ के मामले में, विशेष रूप से उनके पेशेवर करियर के शुरुआती वर्षों के दौरान, उनके अपने पेशे के अभ्यास से आय हुई हो। लेकिन, उस आधार पर, उन्हें कामकाजी पत्रकारों के रूप में वर्गीकृत करना सही नहीं होगा जब तक उनका घोषित व्यवसाय पत्रकारिता के अलावा अन्य है।" यह ध्यान दिया जाएगा कि विधायिका द्वारा " व्यावसायिक व्यवसाय" अभिव्यक्ति को नहीं अपनाया गया है, इसके बजाय इसने "प्रमुख व्यवसाय" शब्दों का उपयोग किया है। इसीलिए हमारा मानना है कि एक व्यक्ति द्वारा दो अलग-अलग व्यवसायों को अपनाने में लगने वाला

समय निर्णायक नहीं हो सकता है; जो बात निर्णायक होगी वह क्रमशः विभिन्न व्यवसायों से प्राप्त होने वाली आय है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए इच्छुक थी कि यदि अपने करियर के शुरुआती वर्षों में कानून के पेशे का पालन करने वाले व्यक्ति को पत्रकारिता के काम से अधिक पैसा मिलता है और वह धारा 2(b)द्वारा निर्धारित अन्य परीक्षणों को पूरा करता है, उसे केवल इसलिए परिभाषा से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि वह किसी अन्य पेशे का पालन कर रहा है। उस सीमा तक, धारा 2(b) का प्रावधान प्रेस आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिश के एक भाग से अलग है।

अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में, जैसा कि हमने माना है, जरूरी नहीं कि उन्हें धारा 2(b) से बाहर रखा जाए। स्थिति यह प्रतीत होती है कि 1955 के अधिनियम 45 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वेतन समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि समिति ने कुछ अंशकालिक कर्मचारियों को कामकाजी पत्रकार माना है। पैराग्राफ 103 में, समिति ने पाया है कि उसने अंशकालिक संवाददाताओं के लिए एक नियमित वेतनमान या रिटेनर प्रदान किया था, और उसने यह भी कहा है कि उस पैमाने के अनुसार पारिश्रमिक अंशकालिक संवाददाताओं को तभी उपलब्ध होगा, जब परिभाषा के अनुसार हो व इसकी सिफ़ारिशों के भाग II, पैराग्राफ 23 में, उनका प्रमुख व्यवसाय पत्रकारिता हो। समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि समाचार पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा नियोजित कई अंशकालिक

संवाददाता इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे यदि उनका मुख्य व्यवसाय कुछ और है और पत्रकारिता केवल एक अतिरिक्त व्यवसाय है, और इसमें कहा गया है कि अंशकालिक के उक्त वर्ग की समस्या संवाददाता इसके संदर्भ की शर्तों के दायरे में नहीं थे, और इसलिए, इसने उस वर्ग के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की।

अपील की अनुमति दी गई।

प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक पुरवा चतुर्वदी**(न्यायिक अधिकारी)**द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः-यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे ्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।